19082015-ls-ngp-04.qxd 08/20/2015 3:22 PM Page 1

और ... एक शेर

मैं एक दिन बेखयाली में कहीं सच बोल बैठा था
मैं कोशिश कर चुका हूं मुंह की कड़वाहट नहीं जाती
-मुनव्वर राना

लोकमत समाचार
नागपुर, बुधवार, 19 अगस्त 2015

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

सभ्यता सुव्यवस्था से जन्मती है, स्वतंत्रता के साथ बड़ी होती है और अव्यवस्था के साथ मर जाती है. ■ विल डुरान्ट

संपादकीय

मोदी की एक और कूटनीतिक सफलता

चौंतीस साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा ठोस नतीजे लेकर आई है. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस देश के साथ भारत के आर्थिक, रक्षा तथा प्रौद्योगिक संबंध तो मजबूत हुए ही हैं, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमें एक और महत्वपूर्ण साथी मिल गया. दोनों देशों का साझा बयान भी आतंकवाद खासकर पाकिस्तान की धरती पर पनपने व वहां से संचालित होने वाली विध्वंसकारी गतिविधियों के प्रति आगाह करता है. पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के नतीजों पर गौर कर सबक सीखना चाहिए. यह एक ऐसा विश्वव्यापी मुद्दा है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में काफी गहरी हैं और उस देश को तबाह कर रही हैं. यही नहीं आतंकवाद को प्रश्रय देकर पाकिस्तान विश्व मंच पर अलग-थलग पड़ता जा रहा है. संयुक्त अरब अमीरात का परोक्ष रूप से पाकिस्तान को चेताना इस बात का प्रमाण है कि हमारा पड़ोसी मुल्क एक-एक कर अपने मित्रों को खोता जा रहा है. नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के बीच सार्थक बातचीत हुई. संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रधानमंत्री वहां की सरकार को भावनात्मक रूप से हिंदुस्तानियों के साथ जोड़ने में सफल रहे. संयुक्त अरब अमीरात ने जहां मंदिर के लिए जमीन देकर दूसरे धर्मों के सम्मान की अपनी परंपरा को समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर अपने विकास में भारतीयों के रचनात्मक योगदान को स्वीकृति भी प्रदान की. मोदी की कूटनीतिक कुशलता के चलते ही इतनी बड़ी उपलब्धि संभव हो सकी. मोदी की इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन हासिल करना रही. पाकिस्तान तथा दुनिया में जगह-जगह फैले आतंकवादी संगठनों में से कई का धन संयुक्त अरब अमीरात में लगा हुआ है. 1993 के मुंबई बम विस्फोट के मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम का तो व्यापारिक साम्राज्य संयुक्त अरब अमीरात में फैला हुआ है. यहां से अर्जित धन के सहारे ही वह आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण करता है और अपना खौफनाक गिरोह भी चलाता है. मोदी ने भारत के सबसे वांछित अपराधी की रसद बंद करने की प्रक्रिया शुरू करवाने में बड़ी सफलता हासिल की है. यह देश दाऊद की संपत्ति तथा कारोबार की जांच कर उसे जब्त करवाने पर सहमत हो गया है. दाऊद को भारत लाने के तमाम प्रयास अब तक विफल रहे हैं. यदि संयुक्त अरब अमीरात अपने वादे के मुताबिक कार्रवाई करता है तो दाऊद कमजोर हो जाएगा और तब पाकिस्तान भी उसे अपने लिए बोझ समझने लगेगा. ऐसे में दाऊद को गिरफ्तार कर भारत लाना संभव हो जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात से साढ़े चार लाख करोड़ रु. का पूंजी निवेश दोनों देशों के आर्थिक हितों को मजबूत बनाने के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंक सकता है. मोदी संयुक्त अरब अमीरात के शासकों को यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास के रास्ते पर है और इस वक्त भारत में निवेश करना बेहद फायदेमंद होगा. मोदी के अन्य विदेशी दौरों की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात में भी उनकी विपक्ष पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर विवाद हुआ है. विपक्ष उन पर देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है. मोदी की यह अपनी शैली है और उनका हर कदम राजनीतिक नाप-तौल के पलड़े पर रहता है. वह अपनी हर विदेश यात्रा में भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी सरकार तथा भाजपा की छवि और निखरे. उनसे लोग असहमत हो सकते हैं लेकिन मोदी के कूटनीतिक कौशल पर कोई उंगली नहीं उठा सकता. ■■

जायदाद

लघुकथा

गोविंद भारद्वाज

वृद्ध पिता को बीमार पड़े महीनों हो गए लेकिन वे ठीक नहीं हो पा रहे थे. उनकी जायदाद के इकलौते वारिस बेटे को यही तलब थी कि पिताजी जल्दी से मर जाएं और सारी जायदाद उसके नाम हो जाए. लेकिन पिता थे कि मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे.

एक दिन हंसते हुए बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, ''पिताजी के मरते ही सारी जायदाद उनके इस बेटे की हो जाएगी.''

तभी उनका आठ वर्ष का लड़का बोल पड़ा, ''और आपके मरने के बाद यह सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, है न पापा...?

यह सुन दोनों पति-पत्नी अवाक रह गए. ■■

बढ़ते प्रभाव का जयघोष

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

जनता की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है अथवा दैनंदिन के संघर्ष में उसे सत्ता के पाप-पुण्य का हिसाब रखने की इच्छा नहीं रहती. लेकिन सत्ता के भागीदारों को तो अपनी सरकारों के सत्कर्मों की याद रखना चाहिए. सत्ता का मुकुट पहनने वाले बदलते रहते हैं, लेकिन दरबार में कुछ पुराने सलाहकार तो रहते ही हैं. इस दृष्टि से यह बात गले नहीं उतरती कि भारी बहुमत से सत्ता में आए नरेंद्र मोदी के मंत्रणा कक्ष में उनके अपने अग्रजों के सफल प्रयासों की समुचित जानकारी नहीं दी जाती. कहीं ऐसा तो नहीं कि नया इतिहास लिखने की तमन्ना के कारण पुराने पन्नों पर ध्यान न देना ही उचित समझा जाता है?

ऐसा नहीं होता तो अबूधाबी-दुबई में पिछले 34 वर्षों से भारत के शीर्ष नेताओं की गतिविधियों पर खेद व्यक्त करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया जाता कि संघ भाजपा के शीर्षस्थ नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने सन 2003 में संयुक्त अरब अमीरात के शासकों, प्रमुख उद्योगपतियों-पूंजी निवेशकों, प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. यह ठीक है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के पास एक्जीक्यूटिव अधिकार होते हैं और उनकी वार्ताओं-यात्राओं का अपना महत्व है. लेकिन देश के राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक-सामरिक प्राथमिकताओं, सलाह तथा तैयारियों के बाद ही विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं. ऐसा नहीं था कि डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और उनके साथ गई उच्च स्तरीय भारतीय टीम को संयुक्त अरब अमीरात ने कमतर आंका था.

सलाहकारों ने मोदी जी का ध्यान इस तथ्य की ओर भी क्यों नहीं दिलाया कि 1997 में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने ओमान, बहरीन, कुवैत की यात्रा कर अरब देशों से संबंधों को आगे बढ़ाया था. भारत की विदेश नीति का आधार वर्षों के प्रयासों से मजबूत हुआ है. नेहरू-नासिर-टीटो, गुट निरपेक्ष देशों के संगठन, दक्षिण एशिया के सार्क संगठन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और कुशल राजनयिकों ने विश्व राजनीति में भारत को बहुत आगे बढ़ाया है. कलाम साहब की रखी नींव को पक्का करने के लिए 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी. इससे पहले विदेश मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी ने वहां भारत का बिगुल बजाया था. विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में रखी फाइलों का अध्ययन करने पर पता चल सकेगा कि पूर्व राष्ट्रपतियों अथवा अन्य नेताओं की यात्रा कितनी लाभदायक थी. यह तर्क बेहद दु:खद है कि पिछले 34 वर्षों में भारत ने अरब देशों की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया.

बहरहाल, हम मोदीजी की इस यात्रा को भी कम सफल नहीं मानते. उनके पास अद्भुत वाक् चातुर्य और मार्केटिंग कौशल है. दुबई के विशाल स्टेडियम में हजारों भारतीयों का जयघोष सही मायने में भारत के बढ़ते प्रभाव का जयघोष है. इसमें भी थोड़ा योगदान उनकी ही सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 10 से 13 नवंबर 2014 तक हुई संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा में तैयार पृष्ठभूमि का है. श्रीमती स्वराज भले ही इस समय विरोधियों के निशाने पर हैं, लेकिन वह भाजपा के वर्तमान नेतृत्व में सर्वाधिक अनुभवी तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं. दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री 2007 और 2010 में भारत आकर द्विपक्षीय आर्थिक-सामरिक संबंध बढ़ाने के समझौते कर चुके हैं. आखिरकार, संबंधों की ताली दोनों पक्षों के हाथों से बजती है. हमसे अधिक उन्हें भी हमारी जरूरत है. अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. लगभग 72 अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार एक साल में नहीं बढ़ गया. अमीरात में लगभग 26 लाख भारतीय सेवाएं दे रहे हैं. अमीरात की आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है. यही नहीं वे हर साल 15 अरब डॉलर भारत भेजते हैं. संयुक्त अरब अमीरात की अर्थ-व्यवस्था करीब 800 अरब डॉलर की है. उसे पूंजी निवेश के लिए भारत से अधिक सुरक्षित देश और विशाल बाजार कहां मिल सकता है? इसलिए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान साढ़े चार लाख करोड़ की पूंजी लगाने का वादा सही है. वादे तो अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस ने भी कर रखे हैं. जरूरत है - भारत सरकार अपने सिस्टम को सुधारे तथा निवेश के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ तालमेल बनाए. राजनीतिक कटुताओं को बढ़ाकर सवा सौ करोड़ की टीम का नारा खोखला हो जाता है. राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं हो सकते. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आतंकवाद से निपटने, भारत विरोधी संगठनों अथवा कुख्यात अपराधी गिरोह से निपटने के लिए अमेरिका-इजराइल, यूरोप के अलावा रूस, चीन, अरब देशों तथा अफ्रीका को साथ लेना होगा. यह काम केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को करना होगा. ■■

प्रधानमंत्री मोदी के पास अद्भुत वाक् चातुर्य और मार्केटिंग कौशल है. दुबई के विशाल स्टेडियम में हजारों भारतीयों का जयघोष सही मायने में भारत के बढ़ते प्रभाव का जयघोष है.

बुनियादी सुविधाओं से वंचित खिलाड़ी

सुलेखा तिवारी
विश्लेषक

देश में खेलों के विकास तथा इस संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में राज्यसभा की मानव संसाधन समिति ने एक रिपोर्ट दी है. यह रिपोर्ट पिछले 13 अगस्त को राज्यसभा के पटल पर रखी गई. इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकारी प्रयास और संसाधनों का उपयोग सिर्फ फाइलों में बंद है. ओलंपिक खेल सिर पर आ गए हैं लेकिन खेलों के लिए जो संसाधन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना चाहिए था, वह नहीं है. अधिकांशतः जगहों पर टर्फ, दौड़ने के लिए ट्रैक, कोर्ट तथा इनडोर सुविधाओं की हालत खस्ता है.

समिति ने बेंगलुरु खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया तो पाया कि वहां पर इनडोर सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब है तथा सीपीडब्ल्यूडी, जिसको रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, वह भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं. वहां पर तमाम लोगों ने शिकायत की कि सीपीडब्ल्यूडी ने मानक के अनुरूप टर्फ नहीं बिछाया है तथा इनडोर कोर्ट में नया कोर्ट बिछाने का काम काफी दिनों से लटका हुआ है. इस संबंध में समिति ने 1995 में अपनी दी गई सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा है कि उस समय से लेकर अब तक स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है. खेल प्राधिकरण में प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यतः वह लोग संभाल रहे हैं जिनका खेल से कोई लेना-देना नहीं रहा है. इस वजह से वह खेल से जुड़ी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं. समिति ने सिफारिश की थी कि खेल प्राधिकारण में अधिक से अधिक खिलाड़ियों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा क्षेत्रीय केंद्रों की जिम्मेदारी व प्रशासन खिलाड़ियों को ही देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है. क्षेत्रीय केंद्रों को छोटी से छोटी चीजों के लिए दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है तथा खुद वह किसी भी चीज पर निर्णय नहीं ले सकते, जिसकी वजह से टेबल टेनिस स्टेडियम, जिम्नाजियम और बैडमिंटन कोर्ट को काफी खराब हालत में पाया गया. समिति ने दौड़ने वाला ट्रैक स्तरहीन पाया. बड़े आश्चर्य की बात थी कि जब तक दिल्ली से अनुमति नहीं होगी तब तक इन सुविधाओं में सुधार के लिए क्षेत्रीय केंद्र कुछ भी नहीं कर सकते.

समिति ने कोचिंग के विषय में भी अपनी चिंता व्यक्त की तथा कहा कि जहां विदेशी कोच पांच से छह लाख रु. प्रति महीना ले रहे हैं, वहीं अच्छे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय प्रशिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा 30,000 रु. महीना मिल रहा है. यह बहुत ही चिंताजनक और हास्यास्पद है. इस संबंध में बहुत जरूरी है कि प्रशिक्षकों की ग्रेडिंग की जाए तथा भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक हैं उन्हें इस मानक के आधार पर विदेशी प्रशिक्षकों की तरह भत्ता दिया जाए.

भारत में खेल और खिलाड़ियों को अभी भी वह इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. हमारे देश में खिलाड़ियों पर 3 पैसे प्रति व्यक्ति की दर पर खर्च होता है.

इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय खेल विकास निधि के बारे में कही गई है. इस निधि का निर्माण खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की सहायता तथा विकास के लिए किया गया था. 1998 में इस निधि की स्थापना एक विधायी तरीके से संसद द्वारा हुई जिसमें तमाम सार्वजनिक संस्थानों, निजी संस्थानों को कुछ पैसा दान के स्वरूप में देना था. लेकिन इसमें बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया तथा कुछ संस्थानों और एक-दो बैंकों के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया.

भारत में खेल और खिलाड़ियों को अभी भी वह इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. हमारे देश में खिलाड़ियों पर 3 पैसे प्रति व्यक्ति की दर पर खर्च होता है. भले ही देश की जनसंख्या सवा सौ करोड़ हो लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या जमैका जैसे देशों से भी कम है जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धी खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत ही कम मेडल मिलते हैं. ■■

अबूधाबी से दुबई तक की प्रतिध्वनि

अवधेश कुमार
जाने-माने पत्रकार

इस बात की संभावना पहले से थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कई मायनों में सफल होगी और इसे दूरगामी परिणामों वाला माना जाएगा. दुबई में मरहबा नमो यानी मोदी का स्वागत नाम से आयोजित कार्यक्रम के साथ यात्रा के अंत ने वाकई इसे ऐसा बना दिया जिसे भारतवंशी ही नहीं वहां के निवासी भी वर्षों याद करेंगे. वैसे तो मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के साथ भारतवंशियों को संबोधित करने का कार्यक्रम अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया है. जहां भी भारतवंशियों की तादाद है वहां ऐसे कार्यक्रम वे करते हैं और उसका प्रबंधन और प्रस्तुति इतनी प्रभावी होती है कि लोगों की बड़ी संख्या कुछ समय के लिए भावविभोर या यों कहें चमत्कृत हो जाती है. दुबई के क्रिकेट स्टेडियम का संबोधन उसी श्रेणी का था.

दुबई में मरहबा नमो यानी मोदी का स्वागत नाम से आयोजित कार्यक्रम के साथ यात्रा के अंत ने वाकई इसे ऐसा बना दिया जिसे भारतवंशी ही नहीं वहां के निवासी भी वर्षों याद करेंगे.

वास्तव में संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, संपन्न समझौतों, साझा वक्तव्य, दुबई में उतनी बड़ी संख्या के बीच उद्बोधन और उसकी विषय वस्तु ने कम से कम चार बातों की फिर से पुष्टि की है. पहला, कुछ लोगों की यह सोच गलत साबित हुई है कि इस्लामी देशों में मोदी को सफलता नहीं मिलेगी. बांग्लादेश से आरंभ कर, मध्य एशिया के चार और अब संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा ने इस दुष्प्रचार का जवाब दे दिया है. हवाई अड्डे पर शहजादे नहयान ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी की अगवानी की. शहजादे के साथ उनके पांच भाई भी मौजूद थे.

दूसरे, घरेलू स्तर पर चाहे जितने मतभेद हों, मोदी दुनिया को यह संदेश देने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं कि उनके नेतृत्व में एक स्थिर और स्थायी सरकार है जो निर्णय करती है. आखिर संयुक्त अरब ने अगर करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है और वहां के अन्य निवेशक भी भारत में काम करने पर विचार करने को तैयार हुए तो इस संदेश के कारण ही. तीन, अपनी बात यानी भारत की सोच को स्पष्टता से रखने में वे हिचकते नहीं और उसके अनुसार कुछ परिणाम भी लाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात में आतंकवाद पर उतना मुखर वक्तव्य एवं खुलकर बातचीत सामान्य घटना नहीं है. आप देख लीजिए संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद पर वो सारी बातें कही गईं हैं जो भारत की दृष्टि से अनुकूल थे. और चौथी बात, सबसे बढ़कर जहां भी भारतवंशी हैं उनको देश के साथ जोड़ने एवं भारत के लिए काम करने को प्रेरित करने तथा उनके संबोधन के द्वारा स्वयं उस देश को या उसके माध्यम से दूसरे देशों को भी उचित संदेश की वे कोशिश करते हैं. ■■

नजर के पार

सैनिक, समाज और देश का दायित्व

डॉ. जे. ए. खान
विभागाध्यक्ष, रक्षा व सामरिक अध्ययन
भोंसला मिलिट्री कॉलेज नाशिक-5

समाज जीवित रहने के लिए होता है और सैनिकों का अस्तित्व इस जीवन की रक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए होता है. इस प्रकार, सशस्त्र बल एक राष्ट्र/राज्य प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और यह संस्था उतनी ही पुरानी है जितना समाज. सशस्त्र बल असामान्य स्थितियों को सामान्य बनाते हैं और अप्रत्याशित स्थितियों में उम्मीद बंधाते हैं.

भारत में, आजादी के बाद से ही, सशस्त्र बलों के अराजनीतिक होने पर गर्व किया जाता रहा है और उन्होंने राष्ट्र की 'नियति के साथ साक्षात्कार' की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पूरी तेजी से सभी कार्य निष्पादित किए हैं और गौरवशाली उपलब्धियां अर्जित की हैं.

सैनिकीय मांग चरम बलिदान मांगती है और चरम बलिदान के लिए चरम मूल्यों से लगाव होना आवश्यक है. यह संभव नहीं हो सकता अगर सैनिकों का राष्ट्रीय नेतृत्व में विश्वास ढीला हो. वर्तमान में दो ज्वलंत मुद्दे देश के सैन्य वातावरण को खराब कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने 'देरी और इनकार' करने की रणनीति का विकल्प चुना है.

सबसे पहले, भारतीय सशस्त्र बल में आधुनिकीकरण कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि न तो पिछली सरकार पर्याप्त बजट आवंटन के बारे में गंभीर थी और न ही वर्तमान सरकार है. पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, किसी भी प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक स्तर तक रक्षा तैयारियां करने के बारे में गंभीरता नहीं दिखाई है. आधुनिकीकरण के नाम पर प्रतिक्रियाशील रक्षा नीति के रूप में सिर्फ कुछ अस्थायी उपाय कर दिए जाते हैं.

सिर्फ इंदिरा गांधी का ही एक सुनहरा काल था जब बेहतर नागरिक-सैन्य संबंधों को बनाए रखा गया था और राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व के बीच सामंजस्य के फलस्वरूप ही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश में परिवर्तित हुआ था.

आज, सेना को आधुनिक टैंकों और बंदूक की जरूरत है, नौसेना को आधुनिक पनडुब्बियों की जरूरत है और वायु सेना की 45 लड़ाकू स्क्वाड्रनों की पिछली स्वीकृत संख्या को पूरा करने की जरूरत है जो 30 तक नीचे आ गई है और जिसमें एसयू-30 को छोड़कर लगभग सभी अग्रचलित विमान हैं. इसके कारण भारतीय वायु सेना भविष्य में चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर किए जाने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब देने की स्थिति में नहीं है. दूसरी ओर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच चल रही खींचातानी समाज और देश में सशस्त्र बलों की छवि को खराब कर रही है. अधिकतर देशों में वन रैंक वन पेंशन लागू है. भारत में भी सशस्त्र बलों को छोड़कर सिविल सेवा में वन रैंक वन पेंशन की अवधारणा को कार्यान्वित किया जाता है. वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई पिछले 20 वर्षों से चल रही है.

मुझे लगता है कि रक्षा तैयारियों और वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन में देरी से देश राजनीति-सैन्य आपदा की ओर बढ़ रहा है. वह दिन आ सकता है जब अराजनीतिक भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो जाएगा और पाकिस्तान की तरह भारतीय सेना के राजनीतिकरण की आशंका भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है. ■■

तोल बोल

हमने राकांपा के लिए बिहार में तीन सीटें छोड़ी हैं. अब हमारे बजाय उसे तय करना है कि वह धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन में रहना चाहती है या नहीं.

■ नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

कांग्रेस ने जो दाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाने की कोशिश की, उसे जनता ने धो दिया है.

■ विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा उपाध्यक्ष

gñWinH¦ gnXH¦ :
ñd. Odñabnb XS¦
M`à Z, E[SQñ{à`b ~¦S :
{dO¯ XS¦
E[SQà-BZ-Mr\¦ :
aOB XS¦
gnXH :
{dH¦rg {_ I ★
★ nr. Aa. ~r. HbZZ H¦
AZgà gnU gnXH¦s` Xq{`Ed
H¦ {bE {Oà_Xa.

© लोकमत समाचार _ àHñ{eV g^r gr_Jr H¦ gdñ{YH¦a bñH¦_V
r{S`ï àñ`dO {b. H¦ mg ga{j V h.
bñH¦_V _r{S`ï àñ`dO {b. H¦ {bE _ÐH¦ Ed àH¦eH¦ बालाजी मुले Ûàar
bñH¦_V _r{S`ï àñ. {b., ñbñQ H¦. 192, 207, 208 E _. AñB. Sr. gr.
B¦S{ñQ` b E[à`ï, ~Qr~rar, ZxJna _{ÐV Ed bñH¦_V ^dZ n.
Odñabnb Zñè¦ _¦J, ZxJna _ àH¦r{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÛd{Z : 0712-2423527 (7 bñB'g) \¦Sg : 6618555
Email : gnXH¦s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 19 अगस्त

आज ही के दिन 1991 में केजीबी प्रमुख समेत आठ कम्युनिस्ट अधिकारियों ने सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाच्येव को सत्ता से बेदखल कर-के एक आपात समिति का गठन किया था. इस मुहिम के बाद गोर्बाच्येव को हिरासत में ले लिया गया था और मॉस्को की गलियों में टैंक प्रवेश कर गए. रेडियो पर घोषणा कर लोगों से कहा गया कि गोर्बाच्येव 'खराब स्वास्थ्य की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं.' सोवियत संघ के न्यूज चैनलों ने गोर्बाच्येव की नीतियों की आलोचना भरी खबरें चलानी शुरू कर दीं. केजीबी प्रमुख समेत आठ कम्युनिस्ट अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि वे देश को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं. इसके बाद दिसंबर में सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस ने खुद को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया. ■■

- 1757-ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार कलकत्ता (अब कोलकाता) में एक रुपए का सिक्का ढाला.
- 1796-स्पेन तथा फ्रांस ने ब्रिटेन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए.
- 1919-अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की.
- 1949-भुवनेश्वर उड़ीसा (अब ओडिशा) की राजधानी बना.
- 1966-तुर्की में भूकंप से 2400 की मौत.
- 1970-दक्षिण अफ्रीका में चीनी समुदाय के लोगों को श्वेत का दर्जा मिला.
- 2013-फिलिस्तीन के राफाह में हमले में मिस्र के 24 पुलिसकर्मियों की मौत.

पाठकों के पत्र

कट्टरपंथियों की धमकी

बांग्लादेश में तीन ब्लॉगरों की हत्या और भारत में पत्रकारों को जिंदा जलाए जाने की खबरों से आतंकित बुद्धिजीवी डर गए हैं शायद, तभी तो लेखन में आकाश-पाताल एक करने वाले लेखक-कवियों ने पहले तो अन्ना आंदोलन से दूरी बनाई थी और अब कट्टरपंथियों की धमकी से अमेरिका जाने पर मजबूर तस्लीमा के हक में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं. साहित्यकार चाहे बांग्ला के हों या हिंदी के, जो तस्लीमा के समर्थन में जुलूस निकालते, नारे लगाते थे वे कहां हैं?

■ इंदिरा किराल्लय, नागपुर

पड़ोसी देश से सावधान

कहते हैं पड़ोसी अच्छे हों तो हम शांति से रहते हैं. पड़ोसी शातिर होने पर हमें हमेशा सतर्क रहना होता है. धर्म के नाम पर भेदभाव करना और एक दूसरे का कट्टर विरोधी बनना देश और दुनिया के लिए कदापि हितकारी नहीं है. हमारा पड़ोसी जब देखो तब सीमा पर गोलीबारी करता रहता है. उससे हमें सतर्क रहना होगा.

■ विनोद नायडू, बल्लारशाह

आप भी अपने पत्र हमें lsedit.ngp@lokmat.com पर मेल कर सकते हैं या डाक पते पर भेज सकते हैं.

सादगी की मिसाल

रुपं: दौर में होने वाले हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे. देश भर से अनेक व्यक्ति उसमें भाग लेने के लिए आए थे. अतिथियों के सम्मान में वहां के सेठ हुकुमचंद ने एक शानदार भोज का प्रबंध किया था.

प्रसंग

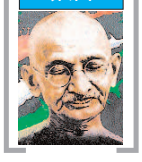

इस भोज के अवसर पर बैठने के लिए जो कुर्सियां बिछी थीं, उनमें चांदी का प्रयोग किया गया था. खाने की सामग्री रखने के लिए सोने की तश्तरियां थीं. लेकिन गांधीजी तो अपने साथ अपनी तामचीनी की तश्तरी और मिट्टी का प्याला लेकर आए थे. जेल में वह इन्हीं बर्तनों का प्रयोग किया करते थे.

सेठ हुकुमचंद ने उनसे प्रार्थना की, ''महात्माजी, कृपा करके आज के दिन तो आप मेरी तश्तरियों में खाना खा लीजिए.''

गांधीजी को शान-शौकत से जरा भी प्रेम नहीं था. वह मुस्कुराए और बोले, ''अगर मैं इन तश्तरियों में खाना खाऊंगा, तो इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा.'

और उन्होंने अपनी ही तश्तरी में ही खाना खाया. ■■